(b) if so, the details thereof Statewise and since when and the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that some of the Bills have been pending for more than eight years; and

(d) if so, the details thereof and the reasons for the delay in obtaining President's assent?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRl BUTA SINGH): (a) and (b) The information sought is given in the attached statement *[See* Appendix CXLDC, Annexure No. 182].

(c) No Bill is pending fpr over eight years for obtaining the President's assent.

(d) Does not arise.

राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा विधेयक

3602. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करने की शक्ति को राज्य सरकार में निहित किये जाने के संबंध में एक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था, यदि हां, तो कब ; और

(ख) क्या उस विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है, यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करने की शक्ति को राज्य सरकार में निहित किए जाने के संबंध में अभी तक कोई विधेयक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश की यात्राएं

3603. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987, 1988 और 1989 के वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों की यात्रा की और ये यात्राएं कितनी बार कीं;

(ख) इनमें से कितनी यात्राएं सरकारी, निजी या राजनीतिक यात्राओं के रूप में वर्गीकृत की गयीं; और

(ग) इन यात्राओं पर केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा, अलग-अलग कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी?

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**

(ग) प्रधानमंत्री दौरे के लिए भारतीय वायुसेना का एयर-क्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। निजी उद्देश्यों के लिए की गयी यात्राओं के लिए निर्धारित दरों पर वसूली की जाती है। जब प्रधान मंत्री राज्यों का दौरा करते हैं तो उनकी सुरक्षा और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रबन्ध राज्य सरकारें करती हैं। इन मुद्दों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के बारे में सूचना केन्द्र सरकार द्वारा संकलित नहीं की जाती है।